आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 05.10.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य सरकार ने प्रदेश के एक हजार 983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया।
- प्रदेशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रव्यापी ''आपकी पूंजी आपका अधिकार'' अभियान शुरू किया।
- चमोली जिले के सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली।

राजस्व ग्राम पुलिसिंग

प्रदेश सरकार ने राज्य के एक हजार 983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में शामिल करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के बाद ग्रामीण और सीमांत इलाकों में सीधे नियमित पुलिस व्यवस्था लागू होगी। इससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और न्याय की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और विश्वास में वृद्धि होगी तथा पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनेगी।

अभियान शुरू

प्रदेशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। यह कदम राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद उठाया गया है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी जिलों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी तत्काल लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औषधि निरीक्षक सिरप के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराएं और दोषपूर्ण दवाओं को बाजार से हटाएं। साथ ही, चिकित्सकों से अपील की गई है कि वे बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें।

भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं के सामान्य उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है। विशेषज्ञ की सलाह और सही खुराक में ही दवा दी जा सकती है। विशेष रूप से डेक्सट्रोमेथोर्फन युक्त सिरप और क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट तथा फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड संयोजन वाली दवाएं चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनता से अपील की है कि डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को दवा न दें और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।.आकाशवाणी समाचार, देहरादून

विरासत महोत्सव शुभारंभ

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कल डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेडियम ओएनजीसी, देहरादून में 30वें विरासत आर्ट एंड हेरिटेज फेस्टिवल का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस की लोकधुनों के साथ देश–विदेश की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी।

महोत्सव की शुरुआत सरोद वादक पद्मविभूषण उस्ताद अमजद अली खान की प्रस्तुति से हुई। उनकी सरोद और तबले की जुगलबंदी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन भारत और विशेषकर उत्तराखण्ड की समृद्ध परंपराओं और गौरवशाली विरासत का उत्सव है। उन्होंने युवाओं से अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि जब नई पीढ़ी अपनी संस्कृति को आत्मसात करती है, तभी वह आत्मविश्वास से विश्व मंच पर खड़ी हो सकती है।

सहकारिता महोत्सव

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सहकारिता महोत्सव की शुरुआत अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान से हुई। कार्यक्रम में अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री व सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया।

उन्होंने बताया कि सहकारिता मेलों का आयोजन प्रदेश के सभी 13 जिलों में किया जा रहा है और इसका समापन दिसंबर में देहरादून में होगा। उन्होंने कहा कि इन मेलों के तीन मुख्य लक्ष्य हैं, जिनमें किसानों को बाजार उपलब्ध कराना, तीन लाख लखपति दीदियों को तैयार करना और मंडुवा, झिंगोरा, धान, बाजरा जैसे अनाजों को वैश्विक पहचान दिलाना शामिल है।

डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारिता से महिला समूहों को 10 लाख रुपये तक और एकल महिलाओं को 21 हजार से 1 लाख रुपये तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठेले वालों, फड़ लगाने वालों और छोटे काश्तकारों को भी प्रतिदिन 5 हजार रुपये तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा।

संशोधन

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम–2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टटैग के बगैर शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हे आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का दो गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान यूपीआई द्वारा जाता है तो आधिकारिक शुल्क का सवा गुना भुगतान करना होगा। यह नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होंगे।

आपकी पूंजी आपका अधिकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुजरात के गांधीनगर से राष्ट्रव्यापी ''आपकी पूंजी आपका अधिकार'' अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अभियान लावारिस जमाराशियों की उनके वैध दावेदारों को उचित वापसी सुनिश्चित करेगा।

स्वीकृति

चमोली जिले के सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्रीमंडल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाड़ गांव में लंबे समय से क्षेत्रीय जनता की मांग पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के प्रयास किए जा रहे थे। विद्यालय की स्थापना से अब सीमांत क्षेत्र के छात्रों को बेहतर और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध होगी तथा क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और शिक्षकों को प्रशिक्षण व नवाचार से जोड़कर छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

अफवाह पर स्पष्टीकरण

माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने नियुक्तियों और स्थानान्तरण को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को निराधार और भ्रामक बताया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 692 पदों में से 50 प्रतिशत पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सीमित विभागीय परीक्षा से भरे जाने हैं। आयोग की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और परीक्षा की तिथि भी निर्धारित है, लेकिन अभी परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है। ऐसे में नियुक्ति में पैसे के लेन–देन की बातें पूरी तरह निराधार हैं।

स्थानान्तरण को लेकर उन्होंने कहा कि विद्यालयों के कोटीकरण का मामला उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। इसलिए शैक्षिक सत्र 2025–26 में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के तहत कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद भ्रामक बातें फैलायी जा रही हैं।

डॉ. सती ने कहा कि नियुक्ति और स्थानान्तरण से जुड़ी छूटी अफवाहें विभाग की छवि धूमिल करने का प्रयास हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शुल्क माफी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सात से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट पहली अक्टूबर से लागू की गई है और एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग छह करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विद्युत लाइन भूमिगत कार्य

बरसात के बाद अब देहरादून में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के कार्य में तेजी आएगी। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एडीबी परियोजना के तहत शहर के मुख्य मार्गों की उपरिगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है।

बारिश के दौरान यह काम अस्थायी रूप से रोका गया था, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा उनमें राजपुर रोड, रामाडा होटल से बल्लुपुर चौक, ट्रांसपोर्ट नगर चौक, लक्खीबाग से ग्राफिक एरा चौक, कमला पैलेस से निरंजनपुर चौक, शिमला बाईपास से सेंट जूड चौक, विधानसभा, कैलाश अस्पताल, कोरेनेशन अस्पताल, बसंत विहार और रिस्पना क्षेत्र शामिल हैं।